मध्यप्रदेश शासन

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष

2008—2009

अनुक्रमणिका

	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
भाग –एक		
1.1	विभागीय संरचना	1
1.2	अधीनस्थ कार्यालय	1
1.3	विभाग के अधीन आने वाले उपक्रम/संस्थाओं का विवरण	1
1.4	विभाग के दायित्व	9
1.5	विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी	9
1.6	सामान्य या प्रमुख विशेषताएं	10
1.7	महत्वपूर्ण सांख्यिकी	10
भाग –दो		
2.1	बजट विहंगावलोकन	11
2.2	बजट प्रावधान, लक्ष्य, व्यय	11
भाग –तीन		
3.1	राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	12
3.2	वर्ष के दौरान विभाग की उपलब्धियॉ	15
भाग –चार		
4.1	सामान्य प्रशासनिक विषय	18
भाग –पॉच		
5.1	अभिनव योजना	18
भाग –छः		
6.1	विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन	18
भाग –सात		
7.1	सारांश	19

मध्यप्रदेश शासन

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2008–09

मंत्रालय

विभाग का नाम	–	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्री का नाम	–	श्री कैलाश विजयवर्गीय
सचिव का नाम	–	श्री अनुराग जैन
वि ोश कर्तव्यस्थ अधिकारी का नाम	–	श्री अनुराग श्रीवास्तव

विभागाध्यक्ष

विभाग के अधीन कोई विभागाध्यक्ष नहीं है ।

भाग एक

1.1 – विभागीय संरचना

विभागीय संरचना एवं विभाग के अन्तर्गत आने वाले निगम/संस्थायें

मंत्री	
सचिव	
निगम	संस्थायें
1. म.प्र. राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड 2. ऑप्टेल टेलीकम्यूनिकेशन्स लिमिटेड	1. म.प्र. एजेन्सी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी (मैप–आईटी)

1.2 अधीनस्थ कार्यालय

विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में कोई विभागाध्यक्ष कार्यालय एवं मैदानी संरचना नहीं है तथा इसका कार्य विभाग के अधीन मध्यप्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (एम.पी.एस.ई.डी.सी.)/म.प्र. एजेन्सी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी (मैप–आईटी) के माध्यम से संपन्न कराया जाता है ।

1.3 विभाग के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण

विभाग के अधीन निम्नानुसार निगम/संस्था कार्यरत हैं :–

1.3.1 मध्यप्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड

मध्य प्रदेश में इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के त्वरित विकास एवं उन्नति हेतु उपयुक्त वातावरण बनाना इस संस्था का उद्देश्य है। निगम की कुल अधिकृत अंशपूंजी रू 3000.00 लाख है एवं प्रदत्त अंशपूंजी रूपये 2191.25 लाख है। निगम को वर्ष 1992–93 के पश्चात राज्य शासन द्वारा कोई पूंजी प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान स्थिति में निगम का संचय एवं आधिक्य रूपये 162.92 लाख है। निगम के वर्ष 2006–2007 के लेखे सांविधिक अंकेक्षण एवं महालेखाकार द्वारा लेखा परीक्षण के उपरान्त निगम की वार्षिक साधारण सभा में स्वीकृत होकर विधान सभा के वर्तमान बजट सत्र में पटल पर रखे जाऐंगे। वर्ष 2007–08 के लेखों का सांविधिक अंकेक्षण कार्य जारी है। मध्यप्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि. की वित्तीय स्थिति **प्रपत्र–क** में अंकित है।

निगम द्वारा प्रवर्तित कम्पनियों में ऑप्टेल टेलीकम्युनिकेशन्स लि. एवं फुजित्सु ऑप्टेल लिमिटेड प्रमुख हैं। म.प्र. में इलैक्ट्रॉनिक्स उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी के विकास एवं संवर्धन के लिए निर्दिष्ट एजेन्सी होने के कारण निगम अधोसरंचना संवर्धन एवं विकास की निम्नलिखित गतिविधियों में कार्यरत हैः–

1.3.1.1 स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (SWAN)

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से इस परियोजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 340 Points of Presence (POP) केन्द्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। परियोजना से ब्लाक जिला से तथा जिला संभाग से तथा संभाग से भोपाल नेटवर्क से जुड़ जायेंगे तथा हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी उपलब्ध हो जाएगी।

1.3.1.2 सामान्य सेवा केन्द्र (Common Service Centre)

भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन की संयुक्त भागीदारी से प्रदेश में कॉमन सर्विस सेन्टर (CSC) की परियोजना प्रारम्भ की जा रही है । इस परियोजना की कुल लागत रूपये 14641.00 लाख रखी गई थी। पी.पी.पी. के माध्यम से इस योजना के क्रियान्वयन में मात्र रूपये 1230.00 लाख का व्यय होगा। गाँवों तक सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों को पहुँचाने के लिए 9232 कॉमन सर्विस सेन्टर की स्थापना की जाना है। इसके अंतर्गत म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (योजना की क्रियान्वयन एजेन्सी) द्वारा एक पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार परियोजना के संभागवार संचालन हेतु निजी भागीदार संस्थाओं का चयन किया गया है। ये संस्थाऐं हैं 3i Infotech (होशंगाबाद संभाग), AISECT (चंबल, सागर एवं रीवा संभाग), CMS Computers (ग्वालियर एवं भोपाल संभाग), NICT (इन्दौर एवं उज्जैन संभाग), Reliance Communications (जबलपुर संभाग)। इन संस्थाओं द्वारा कॉमन सर्विसेस सेन्टर की स्थापना के लिए कार्यवाही प्रारंभ की गई है। अब तक लगभग 3089 सेन्टरों की स्थापना हो चुकी है।

1.3.1.3 इलैक्ट्रॉनिक्स टेस्ट एवं डेव्हलपमेंट सेंटर (ई.टी.डी.सी.)

निगम द्वारा इंदौर तथा भोपाल में केलीब्रेशन का कार्य किया जा रहा है। विभिन्न स्थानों जैसे गुना, मंडीदीप, पीथमपुर एवं देवास में केलीब्रेशन हेतु शिविरों का आयोजन किया गया है। निगम को केलीब्रेशन के लिए **एनएबीएल प्रमाण** पत्र जनवरी 2007 में प्राप्त हुआ था। इसके नवीनीकरण हेतु सर्विलियन्स ऑडिट दिसम्बर 2008 में किया गया जिसमें केलीब्रेशन का कार्य संतोषजनक पाया गया है।

1.3.1.4 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क – इन्दौर

निगम द्वारा वर्ष 1995–96 में इंदौर में स्थापित सॉफ्टेवयर टेक्नोलॉजी पार्क अब पूर्ण रूप से कार्यशील हो चुका है। इस पार्क का लगभग 80,000 वर्गफुट के क्षेत्र उपयोग किया जा रहा है। इस पार्क में मेसर्स कम्प्यूटर साईन्स कार्पोरेशन इंडिया प्रा. लि. जो कि साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रमुख **फॉरचुन 500** कम्पनी है एवं कम्प्यूटर साईन्स कार्पोरेशन की सहायक कम्पनी है द्वारा अपनी इकाई 61,000 वर्ग फुट क्षेत्र में स्थापित की गई है। इससे निगम को रू 1.50 करोड़ प्रतिवर्ष की आय प्राप्त हो रही हैं।

1.3.1.5 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (एसईज़ेड) – भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर।

भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर में राज्य शासन द्वारा आवंटित भूमियों पर इन्फरमेशन टेक्नोलॉजी एस.ई.ज़ेड. की स्थापना का कार्य पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के आधार पर करने के प्रयास जारी है। इसके लिये भागीदार के चयन की प्रक्रिया जारी है। वैश्विक मंदी के कारण इस प्रक्रिया में विलंब हो रहा है।

इसके अतिरिक्त ग्वालियर में 20 एकड़ भूमि पर आई.टी. पार्क की स्थापना की जा रही है। जिसका निर्माण कार्य म.प्र. गृह निर्माण मण्डल के माध्यम से किया जा रहा है।

1.3.1.6 मंत्रालय में कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

मंत्रालय में शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु निगम द्वारा मंत्रालय में कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है। इस केन्द्र में मार्च 2005 से कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है। निगम द्वारा अभी तक 1200 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

निगम इस प्रशिक्षण केन्द्र में ऑरेकल एवं माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से उच्च प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए प्रयासरत् है।

चित्र– मंत्रालय स्थित कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र

1.3.1.7 स्टेट डाटा सेन्टर

भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन की संयुक्त भागीदारी से रूपये 60.00 करोड़ की लागत से स्टेट डाटा सेन्टर की स्थापना की जा रही है। इस सेन्टर में शासन के विभिन्न विभागों का डाटा सुरक्षित रूप से रखा एवं उपयोग किया जा सकेगा।

1.3.1.8 कॉल सेन्टर की स्थापना

निगम द्वारा आम नागरिकों को शासन की योजनाओं की जानकारी देने एवं उनकी शिकायतें दर्ज करने हेतु एक अत्याधुनिक कॉल सेन्टर की स्थापना की गई है। प्रदेश का कोई भी नागरिक टॉल फ्री नंबर 155343 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है एवं आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता है।

1.3.1.9 अन्य गतिविधियॉ

निगम द्वारा शासन के विभिन्न विभागों के लिए इलैक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेन्ट्स खरीदने व कम्प्यूटराईजेशन आदि कार्यों के लिए परामर्श सेवाऐं जैसे कार्य भी किए जा रहे हैं। निगम द्वारा वर्तमान वर्ष में इलैक्ट्रॉनिक्स सामग्री जैसे कम्प्यूटर एवं आई.टी. सॉल्यूशन (नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर आदि) शासन के विभिन्न विभागों को प्रत्यक्ष उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। निगम द्वारा शासन के आदेशानुसार

विभिन्न सेमीनारों/प्रदर्शनियों में भाग लिया गया एवं इनका आयोजन किया गया है।

1.3.1.10 निगम द्वारा प्रवर्तित कम्पनियों का कार्य निष्पादन

(i) फुजुत्सु ऑप्टेल लिमिटेड (फोटेल)

वर्तमान में इस कम्पनी में निगम का कुल निवेश दिनांक 31.03. 2008 तक रू 1368.00 लाख है। कम्पनी द्वारा वर्तमान वर्ष तक लाभांश की घोषणा नहीं की गई है।

फुजुत्सु ऑप्टेल लि. को समीक्षा वर्ष 2007–08 में रू 19.34 लाख की हानि (गत वर्ष रू 93.80 लाख की हानि) हुई है। कम्पनी को कर के पश्चात हानि 33.21 लाख (गत वर्ष रू 672. 30) लाख की हानि) हुई है। निगम इस कम्पनी में अपनी पूंजी के विनिवेश हेतु प्रयासरत है।

(ii) ऑप्टेल टेलीकम्युनिकेशन्स लिमिटेड

म.प्र. राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम की सहायक कम्पनी ऑप्टेल टेलीकम्युनिकेशन्स लि. की अधिकृत अंशपूंजी रूपये 2500.00 लाख है एवं प्रदत्त अंशपूँजी रूपये 2396.71 लाख है। इसकी अंशपूंजी में म.प्र. राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम का निवेश 65.40 प्रतिशत है शेष अंशपूंजी पब्लिक, मे. फुरूकावा एवं अन्य की है। कम्पनी ने पूर्व में ऑप्टिकल फाइबर के क्षेत्र में काफी सराहनीय कार्य किया है। कम्पनी ने गुणवत्ता में आईएसओ 9001 एवं 9002 प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया था। वर्तमान में कम्पनी वित्तीय संकट से जूझ रही है एवं विगत लगभग 9 वर्षों से उत्पादन गतिविधियाँ पूर्णतः बंद हैं। कम्पनी वर्ष 1997–98 से 2007–08 तक लगातार घाटे में है और वर्ष 2007–08 तक कुल संचित हानि लगभग रू 122.25 करोड़ हो चुकी है। कम्पनी की वित्तीय स्थिति **प्रपत्र–ख** में उल्लेखित है।

म.प्र. राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि. द्वारा ऑप्टेल टेलीकम्युनिकेशन्स लि. के विनिवेश के लिए गंभीर प्रयास किए गए किन्तु सभी प्रयास व्यर्थ रहे। किसी भी बिडर्स द्वारा अंतिम प्रक्रिया में भाग न लेने के कारण अंततः विनिवेश की प्रक्रिया बंद कर दी गई।

कम्पनी के संचालक मण्डल द्वारा दिनांक 01.06.2005 से कम्पनी में तालाबंदी घोषित कर दी गई। कम्पनी की नेटवर्थ भी ऋणात्मक हो जाने के कारण कम्पनी को बीमार औद्योगिक अधिनियम की धार 15 (1) के अधीन पुनुरूत्थान हेतु बी. आई. एफ. आर. को अग्रेषित कर दी गई। बी.आई.एफ.आर. द्वारा कम्पनी को पुनुरूत्थान हेतु दिनांक 23.11.2005 को पंजीकृत किया गया तथा कम्पनी को दिनांक 31.03.2004 से बीमार औद्योगिक इकाई घोषित किया जा चुका है। कम्पनी द्वारा पुनुरूत्थान हेतु योजना प्रस्तुत की गई। बी.आई.एफ.आर. द्वारा योजना का परीक्षण करने के पश्चात पाया गया कि एक निश्चित समय में कम्पनी का पुनुरूत्थान संभव नहीं है। बी.आई. एफ.आर. ने सभी संबंधित संस्थानों/कार्यालयों को नोटिस जारी करने के पश्चात कम्पनी के समापन का निर्णय 26.12.2007 को लिया है। आगे की कार्यवाही हेतु मामला माननीय उच्च न्यायालय, म.प्र. में लंबित है।

कम्पनी के वर्ष 2004–05 तक के लेखे विधानसभा पटल पर रखे जा चुके हैं। वर्ष 2005–2006 के लेखे भी अंकेक्षित हो चुके हैं तथा इन लेखों पर महालेखाकार ग्वालियर का प्रमाण–पत्र भी प्राप्त हो चुका है। वर्ष 2006–2007 के लेखों का संकलन हो चुका है। वर्ष 2005–06 के लेखे स्थगित वार्षिक साधारण सभा द्वारा पारित होने के पश्चात् वर्ष 2006–07 के लेखों को संचालक की बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

1.3.2 मध्यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी (MAP_IT)

इस संस्था का गठन वर्ष 1999 में किया गया। यह संस्था मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अन्तर्गत पंजीकृत है। यह राज्य शासन की पंजीकृत सोसायटी है जो राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिये कार्य करती है।

1.3.2.1 मैप आई.टी. के उद्देश्य :–

राज्य सरकार के विभागों/एजेन्सियों को सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी परामर्श देना तथा उन्हें कम्प्युटरीकरण और नेटवर्किंग के कार्यो में सहायता प्रदान करना।

उद्योग तथा निवेशकों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थानों से समन्वय स्थापित कर सूचना प्रौद्योगिकी की प्रगति को बढ़ावा देना। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानव संसाधन के विकास को बढ़ावा देना।

संस्था मान. मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में गठित शासी निकाय के नियंत्रण में कार्य करती है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं। वित्त विभाग के मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा विभाग एवं वित्त विभाग इस शासी निकाय के सदस्य हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी सोसायटी के शासी निकाय के सदस्य सचिव हैं। इस संस्था को राज्य शासन की ओर से दिये गये अनुदान प्रपत्र–ग में उल्लेखित हैं।

1.3.2.2 लेखा परीक्षणों की स्थिति –

मैप आई.टी. के वर्ष 2007–2008 लेखों के अंकेक्षण का कार्य प्रगति पर है तथा वर्ष 2006–07 का अंकेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2003–04 तक के लेखे पंजीयक, फर्म्स एवं सोसायटीज को प्रेषित किये गये है।

1.3.2.3 मैप आई.टी. की उपलब्धियाँ

(i) नेशनल ई–गवर्नेंस प्लान –

भारत सरकार द्वारा यह महत्वपूर्ण परियोजना प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य शासकीय कार्यो में ई–गवर्नेन्स के उपयोग को बढ़ावा देना है। नेशनल ई–गव्हर्नेंस प्लान के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा मैप–आई.टी. को नोडल एजेन्सी बनाया गया है।

(ii) ई–गव्हर्नेन्स रोडमैप तथा ब्ल्यू प्रिन्ट :

शासन के निर्णयानुसार ई–गव्हर्नेन्स प्लान के तहत ई–गव्हर्नेन्स रोडमैप, कैपेसिटी बिल्डिंग रोडमैप एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, नेशनल इर्स्टिट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेन्स हैदराबाद (एनआईएसजी) के माध्यम से तैयार कराया गया है तथा उक्त प्रतिवेदन औपचारिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

(iii) स्टेट ई–गव्हर्नेन्स मिशन मोड दल के विकास के लिए तकनीकी सलाहकार संस्था का चयन :

नेशनल ई–गव्हर्नेन्स प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन द्वारा मैप–आई.टी. को नोडल ऐजेन्सी नियुक्त किया गया है। इस परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन के विभिन्न विभागों का कम्प्यूटराईजेशन किये जाने हेतु मैप–आई.टी. को एसईएमटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार परियोजना के क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सलाहकार संस्था का चयन किया जाना है। भारत सरकार द्वारा सुझाई गई निम्न 4 तकनीकी सलाहकार संस्थाओं से प्रस्ताव प्रस्तुत

करने को कहा गया है :–

1. मेसर्स केपीएमजी
2. मेसर्स आईएल एण्ड एफएस
3. मेसर्स पीडब्ल्यूसी
4. मेसर्स विप्रो

कम्पनियों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रक्रियानुसार सलाहकार संस्था का चयन कर प्रदेश में राष्ट्रीय ई–गव्हर्नेन्स प्रक्रिया को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जायेगा।

(iv) ई–डिस्ट्रिक्ट

प्रथम चरण में यह परियोजना प्रदेश के पांच जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए AS-IS Analysis, Gap Analysis तथा To Be Report पूर्ण हो चुकी है। परियोजना की प्रक्रिया को शासन द्वारा परियोजना अनुमोदन हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। वर्तमान में परियोजना के अंतर्गत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेव्हलपर का चुनाव कर लिया गया है एवं सॉफ्टवेयर डेव्हलपमेंट का कार्य प्रगति पर है। भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पॉचों जिलों के लिए प्रथम किश्त की धनराशि प्रेषित की जा चुकी है तथा द्वितीय किश्त की धनराशि प्रेषित किये जाने की संभावना है।

(v) **मण्डियों का कम्प्युटरीकरण (EKVI) :– ईक्वी परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2007–08 में किये जा रहे कार्यो का विवरण–**

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा उनके समस्त कार्यालयों तथा 230 मण्डियों के कार्यों को चरणबद्ध तरीके से कम्प्युटरीकरण किया जा रहा है। परियोजना प्रदेश की सभी 'ए' एवं 'बी' श्रेणी मण्डियों एवं कुछ 'सी' श्रेणी की मण्डियों में (कुल 64 स्थानों पर) सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।

(vi) **ई–टेंडर**

प्रदेश के सभी विभागों के निविदा संबंधी कार्यों हेतु ई–टेण्डर परियोजना प्रारम्भ की गई है। इस प्रणाली के माध्यम से रूपये 126671.72 लाख की राशि के 270 टेण्डर जारी किये जा चुके है।

(vii) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पुरूस्कारों का वितरण

सूचना प्रौद्योगिकी को बढावा देने के लिये राज्य शासन द्वारा इस क्षेत्र में उत्तम कार्यो के लिये पुरूस्कार देने का निर्णय लिया गया है। विभाग के निर्देशों के परिपालन में मैप–आईटी द्वारा प्रदेश में सूचना

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभाग/कार्यालय/संस्था को 06 जून 2008 को निम्नानुसार उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरूस्कार प्रदान किये गये है:–

Best e-governed district of M.P.	संयुक्त रूप से जिला सिवनी एवं मंडला
Best IT for Masses Project of M.P.	संयुक्त रूप से एग्रीसनेट प्रोजेक्ट, कृषि, किसान कल्याण विभाग एवं ई–सेवा ऑफ ट्रॉन्सपोर्ट प्रोजेक्ट, परिवहन विभाग
Best application software developed in M.P.	संयुक्त रूप से एएमआर/आरएमआर ऑफ हाईवेल्यू कन्सूमर म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं. जबलपुर एवं फायर एलर्ट एण्ड मेसेजिंग सिस्टम एपीपी, वन विभाग
Best exporter of products located and having production facilities in M.P.	मेसर्स यश टेक्नोलॉजी प्रा.लि. इन्दौर

1.4 विभाग के दायित्व

विभाग के दायित्व मुख्यतः निम्नानुसार है :–

(i) सूचना प्रौद्योगिकी, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएँ सम्मिलित हैं।

(ii) समस्त स्तरों पर नागरिक सेवाओं के सुधार के लिए ई–गवर्नेस का संवर्धन।

(iii) राज्य सरकार के समस्त विभागों, नगरीय तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों में सूचना प्रौद्योगिकी, जिसमें कम्प्यूटरीकरण सम्मिलित है, के उपयोग का संवर्धन।

(iv) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, नगरीय तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा नागरिक सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की परियोजनाओं के संबंध में सहायता तथा समन्वय।

(v) जनता के बीच सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को लोकप्रिय बनाना तथा बोधगम्य बनाना।

(vi) राज्य सूचना प्रोद्योगिकी नीति तथा कार्य योजनाओं के कियान्वयन के लिए समन्वय।

(vii) सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेमिनार, कार्यशाला, सम्मेलन का आयोजन।

(viii) कम्प्यूटरों के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तथा हार्डवेयर पार्क से संबंधित औद्योगिक केन्द्रों, सूचना प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और इलैक्ट्रॉनिक्स से संबंधित संचार उपकरणों की स्थापना में अभिवृद्धि तथा सहायता और ऐसे

प्रयासों में निजी भागीदारी को प्रोत्साहन।

(ix) ग्रामीण इंटरनेट तथा अन्य इंटरनेट आधारित सूचना प्रणाली, जिसमें विभिन्न सेवाओं के लिए सूचना बूथों (कियोस्क) तथा आभासी कार्यालयों की स्थापना सम्मिलित है, का प्रोन्नयन।

(x) विभिन्न विभागों के सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों तथा उपयोजनाओं के संबंध में परामर्श।

1.5 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

विभाग भारत सरकार के इंफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एवं म.प्र. सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करता है। विभाग के अधीन वर्तमान में संसदीय कार्य एवं विधि विषयक कार्य नहीं किए गए हैं। विभाग के अधीन कोई न्यायालयीन निर्णय के प्रकरण लंबित नहीं है। विभाग के अधीन कोई संचालनालय/जिला कार्यालय कार्यरत् नहीं होने से विभागीय जाँच पदोन्नति, नियुक्ति, आदि की जानकारी निरंक है।

1.6 सामान्य या प्रमुख विशेषताएँ

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गव्हर्नेन्स प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकता बनती जा रही है। शासन के विभिन्न अंगों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने हेतु विभाग उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। विभाग का प्रयास रहा है कि राज्य शासन के विभिन्न अंगों को आधारभूत अधोसंरचना उपलब्ध कराई जाये। इस दिशा में विभाग ने ठोस प्रयास प्रारम्भ कर दिये हैं। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, कॉमन सर्विस सेन्टर, स्टेट डाटा सेन्टर जैसी अधोसंरचनाऐं अतिशीघ्र विभिन्न विभागों के उपयोग के लिए उपलब्ध करा दी जायेंगी।

प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश को आकर्शित करने हेतु विभाग द्वारा कई कदम उठाए गये हैं। उद्योग विभाग द्वारा निवेश आकर्षित करने हेतु खजुराहो, मुम्बई, बंगलूरू, इन्दौर तथा जबलपुर में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में विभाग द्वारा सक्रिय भागीदारी निभाई गई। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में निवेश का अच्छा वातावरण तैयार हुआ है। प्रदेश में 21 आई.टी. एस.ई.ज़ेड. की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं सागर में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 20 कम्पनियों से रूपये 7700 करोड़ के निवेश हेतु एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किये गये हैं।

1.7 महत्वपूर्ण सांख्यिकी

विभाग के अधीन कोई संचालनालय नहीं है तथा विभाग अन्य विभागों को परामर्श के माध्यम से कार्य करता है। विभाग आवश्यकता पड़ने पर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के बारे में निर्देश जारी करता है।

भाग–दो

2.1 – 2.2 : बजट विहंगावलोकन एवं बजट प्रावधान, लक्ष्य, व्यय (योजनावार)

विभाग को वर्ष 2008–2009 में व्यय हेतु रूपये 43,12,60,000 का बजट प्राप्त हुआ है। वर्ष 2008–09 का कुल बजट प्रावधान एवं योजनावार व्यय की जानकारी निम्नानुसार है:–

बजट प्रावधान वर्ष 2008–2009 एवं योजनावार व्यय

(आंकडे रूपयें में)

मद	आवंटित बजट	व्यय की गई राशि (9.3.2009 तक)
5125–मैप आईटी में जीआईएस लैब की स्थापना 42–सहायक अनुदान 001–अधोसंरचना अनुदान	1,00,00,000	–
6760 –नई तकनीक हेतु मैपिट अथवा अन्य संस्थाओं को सहायता, 42–सहायक अनुदान,002 संधारण अनुदान	1,00,00,000	1,00,00,000
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य 26–सेमीनार, कार्यशाला, सम्मेलन	50,00,000	50,00,000
8808 सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य–24 परीक्षा एवं प्रभिाक्षण, 002 प्रभिाक्षण	10,00,000	10,00,000
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य, 42–सहायक अनुदान, 007–अन्य	39,00,000	26,12,000
5722–कॉल सेन्टर की स्थापना, 42, सहायक अनुदान, 002–संधारण अनुदान	25,00,000	25,00,000
आयोजनेत्तर 5268–एनआईसी जिला केन्द्रें के रख–रखाव–42–सहायक अनुदान 002–संधारण अनुदान	21,60,000	21,60,000
0701–केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 6873–राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स प्लान, 42–सहायक अनुदान,007– अन्य	24,15,00,000	4,08,80,000
6874– स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क की स्थापना 42–सहायक अनुदान,007–अन्य	15,77,00,000	मार्च 2009 तक पूर्ण राशि का उपयोग प्रस्तावित है
योग	43,37,60,000	6,41,52,000

भाग–तीन

3.1 राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

3.1.1 राज्य योजनाएँ

(i) मैप–आईटी में जी.आई.एस. लैब की स्थापना

सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत मैप–आईटी में एक पूर्ण जी.आई.एस. लैब की स्थापना की जाना है। जिसमें मैप सर्वर, वर्क स्टेशन, स्केनर, प्लॉटर एवं मैप डाटा उपलब्ध रहेगा। सभी विभाग अपने अपने स्तर पर उपरोक्त गतिविधि कर रहे हैं जिससे राशि का अपव्यय हो रहा है। उपरोक्त सेन्टर प्रारम्भ होने पर प्रदेश के लिये प्राकृतिक एवं भौतिक अद्योसंरचना संबंधी संसाधन प्रबंध प्रणाली विकसित हो जायेगी। योजना की कुल लागत रूपये 278.86 लाख है। वर्ष 2008–09 में योजनान्तर्गत प्रावधानित राशि रूपये 1.00 करोड़ से केपीटल व्यय किया जायेगा।

(ii) नई तकनीक हेतु संस्थाओं को सहायता–

शासकीय इंजीनियरिंग कॉलज उज्जैन, रीवा, सागर, जबलपुर एवं सरदार वल्लभ पोलीटेकनिक महाविधालय भोपाल में सेन्टर फॉर एक्सीलेन्स की स्थापना का निर्णय लिया गया हैं । निम्नानुसार कंपनियों द्वारा इंजीनियरिंग महाविधालय में इस सेन्टर की स्थापना की जावेगीः–

क्र	इंजीनियरिंग महाविधालय का नाम	कंपनी का नाम
1	इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जबलपुर	आईबीएम
2	इंजीनियरिंग महाविद्यालय, उज्जैन	ऑरेकल
3	इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रीवा	माईक्रोसाफ्ट
4	इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सागर	सिस्को
5	स.वल्लभ पोलीटेकनिक महा. भोपाल	एडोबे

सेन्टर फॉर एक्सीलेन्स के लिए आवश्यक राशि एवं कंपनियों के साथ सहयोग तथा परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पूर्ण किया गया है। इन महाविधालयों को वर्ष 2008–09 में 20–20 लाख की राशि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है। पांचों स्थानों पर कंपनियों के सहयोग से एक स्टेट ऑफ दी आर्ट लैब की स्थापना की जावेगी जिसमें छात्र इस क्षेत्र की दक्षता प्राप्त करेंगे।

3.1.2 **केन्द्र प्रवर्तित योजना**

विभाग में निम्नलिखित केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं संचालित हैः–

(i) **राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स प्लान,**

नेशनल ई–गवर्नेंस प्लान के तहत प्रदेश का ई–गवर्नेन्स रोड मैप एवं ब्ल्यू प्रिन्ट तैयार किया जाकर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। ब्ल्यू प्रिन्ट पर भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति के बाद रोड मैप के अनुसार चयनित विभागों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्य प्रांरभ किया जायेगा। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 में रूपये 2415.00 लाख का प्रावधान किया गया है। परियोजना अन्तर्गत भारत सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार मिशन मोड परियोजनाओं को एकीकृत कर कम्प्यूटराईजेशन के लिए परियोजनाओं की पहचान कर ली गई है (Central MMP, State MMP & Integrated MMP)। भारत सरकार द्वारा राज्य शासन को अपनी आवश्यकता के अनुसार पाँच अन्य परियोजनाओं का चयन करने की अनुमति प्रदान की गई है। परियोजना के तहत वाणिज्यिक कर, स्वास्थ्य, वन, नगरीय प्रशासन एवं विकास, उद्यानिकी, जेल, पुलिस तथा कोष एवं लेखा आदि विभागों को कम्प्यूटराईजेशन के लिए तकनीकी सलाह प्रदान करने की प्रकिया जारी है।

(ii) **स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना,**

भारत शासन द्वारा मध्यप्रदेश के लिए State Wide Area Network (SWAN) अधोसंरचना हेतु राशि स्वीकृत की गई है। उपरोक्त परियोजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि. (एमपीएसईडीसी) द्वारा किया जा रहा हैं। इस परियोजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 340 Points of Presence (POP) केन्द्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। राज्य के सभी ब्लॉक मुख्यालय उनके जिला मुख्यालय से जिला मुख्यालय उनके संभाग मुख्यालय से एवं संभाग मुख्यालय भोपाल से जोड़ने की क्षमता रहेगी। परियोजना की लागत रूपये 17421.00 लाख है, जिसमें भारत सरकार द्वारा योजना में रूपये 11670.00 लाख का अंशदान रहेगा तथा राज्य सरकार द्वारा 5751.00 लाख का अंशदान रहेगा। योजना अंतर्गत मानव संसाधन एवं परियोजना के परिचालन हेतु आवश्यक बैंडविड्थ/कनेक्टिविटी पर राज्य सरकार द्वारा पाँच वर्षो में किये जाने वाला व्यय निम्नानुसार हैः–

कार्य	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
मानव संसाधन एवं आवश्यक बैंडविड्थ / कनेक्टिविटी व्यय	610.13 लाख	1577 लाख	1580 लाख	947.87 लाख	1036 लाख

वर्ष 2008–09 में इस मद अंतर्गत राज्य शासन द्वारा रूपये 15.77 करोड का बजट प्रावधान किया गया है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु प्रारम्भिक किश्त रूपये 12.00 करोड़ की राशि भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। जिलों में Points of Presence (POP) की स्थापना का कार्य पूर्णता पर है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इण्डिया (STPI) को इस परियोजना हेतु सलाहकार नियुक्त किया गया है। एसटीपीआई द्वारा SWAN की डिजाईन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। परियोजना के पाँच वर्ष तक संचालन हेतु उपयुक्त भागीदार का चयन टेण्डर के माध्यम से किया गया है। चयन के पश्चात मेसर्स ट्यूलिप टेलीकॉम लिमिटेड को रूपये 95 करोड़ का कार्यादेश जारी कर दिया गया है। नेटवर्क की स्थापना का कार्य जारी है।

(iii) कॉमन सर्विस सेन्टर की स्थापना–

भारत सरकार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं म.प्र. शासन की संयुक्त भागीदारी से सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों को आम नागरिकों तक पहुँचाने के लिए प्रदेश में 9232 कॉमन सर्विस सेन्टर की स्थापना की जायेगी।

इस परियोजना हेतु म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. को क्रियान्वयन संस्था नियुक्त किया गया है। इन केन्द्रों द्वारा ई–प्रशासन को सुनिश्चित करते हुए आम नागरिकों को कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से उच्च स्तरीय विडियो, विभिन्न डाटा, ई–गवर्नेन्स सेवाऐं, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि की जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी। इस परियोजना से लगभग 18000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होने की संभावना है।

परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जारी निविदा के माध्यम से 5 संस्थाओं का चयन किया गया है। ये संस्थाऐं हैं 3i Infotech (होशंगाबाद संभाग), AISECT (चंबल, सागर एवं रीवा संभाग), CMS Computers (ग्वालियर एवं भोपाल संभाग), NICT (इन्दौर एवं उज्जैन संभाग), Reliance Communications (जबलपुर संभाग)। चयनित संस्थाओं के साथ अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है। अब तक लगभग 3089 सेन्टरों की स्थापना हो चुकी है।

(iv) स्टेट डाटा सेन्टर

भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन की संयुक्त भागीदारी से रूपये 60 करोड़ की लागत से स्टेट डाटा सेन्टर की स्थापना की जा रही है। इस सेन्टर में शासन के विभिन्न विभागों का डाटा सुरक्षित रूप से रखा एवं उपयोग किया जा सकेगा।

(v) ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना

भारत सरकार द्वारा नेशनल ई–गवर्नेन्स परियोजना के तहत प्रदेश में ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना लागू करने का निर्णय है। योजना के क्रियान्वयन के प्रथम चरण में ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, इन्दौर तथा सागर जिलों का चयन किया गया है। मेप–आईटी को इस योजना की नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है। मेसर्स विप्रो लिमिटेड को इस परियोजना के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है। आवश्यकताओं के आंकलन के बाद साफ्टवेयर का विकास प्रारंभ कर दिया गया है । इसका रोल आउट माह अप्रेल तक पूर्ण कर लिया जाएगा ।

3.1.3 विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं

विभाग में विश्व बैक की सहायता से कोई योजना संचालित नहीं है ।

3.1.4 विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं/परियोजनाएं

विभाग विदेशी सहायता से कोई परियोजना नहीं चला रहा है ।

3.2 वर्ष के दौरान विभाग की उपलब्धियॉ

3.2.1 **ई–टेण्डर** :– राज्य शासन द्वारा शासकीय निविदाओं में इलेक्ट्रानिक टेंडरिंग व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के कार्य विभागों के क्रय संबंधी कार्यो हेतु ई–टेण्डर परियोजना प्रारंभ की गई है। मेसर्स विप्रो द्वारा इस परियोजना का क्रियान्वयन किया गया है। योजना का कार्य BOOT (बिल्ड, ओन, ऑपरेट एवं ट्रान्सफर) के आधार पर किया गया है एवं इसमें राज्य शासन पर कोई व्यय भार नहीं आ रहा है। ई–टेण्डरिंग परियोजना अंतर्गत नर्मदा घाटी विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा ऊर्जा विभाग में ई–टेण्डर प्रक्रिया लागू की गई है। इन विभागों के टेण्डर को इस माध्यम से जारी किये गये है। सभी शासकीय विभागों के क्रय कार्य ई–टेण्डरिंग के माध्यम से करने हेतु वेबसाईट उपलब्ध है। इस प्रणाली के माध्यम से रूपये 126671.72 लाख की राशि के 270 टेण्डर जारी किये जा चुके है।

3.2.2 **mponline नामक पोर्टल का विकास**:– राज्य शासन द्वारा सुदूर क्षेत्रों में नागरिकों को कहीं भी कभी भी (Any Time Anywhere) शासकीय सेवाऐं प्रदान करने के लिए mponline नामक पोर्टल विकसित किया गया है www.mponline.gov.in वेबसाईट के माध्यम से व्यावसायिक परीक्षा मंडल के फॉर्म जारी किये गये है। नागरिकों को 352 सूचना गुमटियों के माध्यम से फॉर्म एवं शासकीय जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। एमपी ऑन लाईन द्वारा खसरें की नकल उपलब्ध कराने के लिए डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त साफ्टवेयर एवं Utilization की व्यवस्था बना ली गई है। पायलेट के रूप में भोपाल एवं सीहोर जिलों का डेटा पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। अन्य जिलों का डेटा शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

3.2.3 **प्रदेश में इन्फॉरमेशन टेक्नालॉजी एसईजेड की स्थापना** :– भारत सरकार द्वारा भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर में एम.पी.एस.ई.डी.सी. द्वारा प्रस्तावित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क परियोजनाओं को स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य शासन द्वारा इस परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि उपलब्ध कराई गई है:–

भोपाल में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना हेतु एयरपोर्ट के पास राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समीप ग्राम बड़वई में कुल रकवा 212.63 एकड़ शासकीय भूमि का आवंटन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को किया गया है।

जबलपुर में पटवारी हल्का नं. 28/33 ग्राम पूर्वा की खसरा न. 865/5 की 90 एकड़ भूमि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हेतु आवंटित की गई है। यह भूमि म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल मुख्यालय के पास है।

ग्वालियर में गंगा मालनपुर गाँव की खसरा न. 407, 408 एवं 412 की 12 हेक्टेयर भूमि (लगभग 25 एकड़) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हेतु आवंटित की गई है। यह क्षेत्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट (आई.आई.आई.टी.एम.) के पास है। इसी से लगी हुई लगभग 35 एकड़ भूमि और मिलने की आशा है।

प्रदेश के उपरोक्त तीनों प्रमुख शहरों में चयनित भूमियों पर एस.ई.ज़ेड. की स्थापना का कार्य पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के आधार पर किया जा रहा है। इस कार्य के लिए नियुक्त सलाहकार द्वारा तैयार आर.एफ.क्यू. डाक्यूमेंट को यथोचित स्तर पर अनुमोदन के पश्चात् राष्ट्रीय स्तर पर प्री–क्वालीफिकेशन प्रस्ताव आमंत्रित किये गये। इसके अंतर्गत चार प्रतिष्ठित कम्पनियों को प्री–क्वालीफाई किया गया है।

सलाहकार द्वारा वित्तीय प्रस्ताव एवं कन्सेशन एग्रीमेंट का डाक्यूमेंट तैयार किया गया जिसका अनुमोदन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया गया है। प्री–क्वालीफाईड कम्पनियों से वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं।

ग्वालियर एवं जबलपुर के लिए किसी भी कम्पनी ने वित्तीय प्रस्ताव नहीं दिये। भोपाल के लिए वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त हुआ है एवं मेसर्स यूनिटेक का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। मेसर्स यूनिटेक के साथ कन्सेशन एग्रीमेंट निष्पादित करने की प्रक्रिया जारी है।

इसके अतिरिक्त ग्वालियर में 20 एकड़ भूमि पर आई.टी. पार्क की स्थापना की जा रही है। जिसका निर्माण कार्य म.प्र. गृह निर्माण मण्डल के माध्यम से किया जा रहा है।

3.2.4 सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरूस्कार :–

प्रदेश को गोवा में आयोजित 12वे राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स कान्फ्रेन्स में निम्नानुसार श्रेणीयों में पुरूस्कार प्राप्त हुए है:–

• Innovative Usages of Technology in e-Governance	वन विभाग, द्वारा प्रस्तुत फायर एलर्ट एवं मैसेजिंग सिस्टम (एफ.ए.एम.एस.) परियोजना को रजत पदक (द्वितीय पुरूस्कार) प्राप्त हुआ।
• Exemplary Usages of ICT by Public Sector Undertaking	इस श्रेणी में म.प्र. ईस्ट डिस्कॉम, ऊर्जा विभाग, म.प्र. भाासन द्वारा प्रस्तुत ऑटोमैटिक मिटरिंग प्रोजेक्ट (ए.एम.आर.) को संयुक्त रूप से रजत पदक (द्वितीय पुरूस्कार) प्राप्त हुआ।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य हेतु विशेष उपलब्धियॉ/पुरूस्कार भी प्राप्त हुए है :–

- प्रदेश ई–गव्हर्नेन्स के माध्यम से सुशासन प्रदान करने में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य बन गया है। ई–गव्हर्नेन्स पर दिनांक 18 दिसम्बर 2008 को नई दिल्ली में आयोजित 6वें अंतर्राष्ट्रीय कान्फरेन्स में सीएसआई निहीलेण्ट आवार्ड 2007–08 के प्रतिष्ठित पुरस्कारों में मध्यप्रदेश को ई–गव्हर्नेन्स की बेस्ट श्रेणी के तहत सी.एस.आई. निहीलेण्ट पुरस्कार 2007–08 के लिए प्रथम रनरअप पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य को कम्प्यूटराईजेशन ऑफ मंत्रालय की एक्सलेण्ट प्रोजेक्ट की श्रेणी में भी प्रतिष्टित पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है। उक्त कार्यक्रम में मध्यप्रदेश को सर्वाधिक पुरस्कार विजेता राज्य घोषित किया है।

3.2.5 मंत्रालय में स्थापित लेन को अपग्रेड किया जाना:–

मंत्रालय में स्थापित लेन को अपग्रेड किया जाकर गीगाबाईट लेन की स्थापना की गई है।

भाग–चार

4.1 सामान्य प्रशासनिक विषय

विभाग के अधीन कोई विभागाध्यक्ष तथा जिला कार्यालय नहीं है। प्रशासनिक विषय निरन्क हैं।

भाग–पॉच

5.1 अभिनव योजनाऐं

विभाग द्वारा निम्नानुसार अभिनव योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है :–

1 **स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क की स्थापना**

2 **आईटी एसईजेड की स्थापना**

3 **नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान**

4 **कॉमन सर्विस सेन्टर की स्थापना**

5 **स्टेट डाटा सेन्टर परियोजना**

6 **ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना**

7 **ई–टेंडरिंग परियोजना**

भाग–छः

6.1 विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन

विभाग द्वारा वर्तमान में कोई नियमित प्रकाशन नहीं निकाला जा रहा है किन्तु विभाग की नीतियों एवं शासन के कार्यों के प्रचार–प्रसार के लिए पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया गया है। जिनमें मुख्यतः निम्नानुसार है :–

- Information Technology Policy 2006.
- Advantage Madhya Pradesh
- Best Practices – Successful e-Governance initiatives by State of Madhya Pradesh

भाग–सात

7.1 सारांश

ई–गवर्नेंस वर्तमान परिदृश्य में बेहतर प्रशासन का पर्यायवाची बनता जा रहा है। इस विधा को अंगीकार करना अब एक आवश्यकता बन गया है । इस परिपेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा ई–शासन को लागू करने के लिए अनेक कदम उठाये गए हैं । इसी कड़ी में इन्टरनेट पर प्रदेश से संबंधित उपलब्ध जानकारी को एक स्थल से उपलब्ध कराने के लिए एमपी ऑन लाईन पोर्टल बनाया गया है । राज्य शासन द्वारा प्रदेश के भोपाल ग्वालियर एवं जबलपुर में साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाने का निर्णय लिया है। पार्क निर्माण के बाद सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रशिक्षित मानव संसाधन को रोजगार के अवसर प्राप्त होगें। विभाग शासन के उद्देश्यों एवं नीतियों के प्रभावशील क्रियान्वयन में सफल रहा है।

==========

प्रपत्र–क

1. मध्यप्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है :

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	2002–2003	2003–2004	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08 (अनन्तिम)
सकल आय	643.19	280.28	293.39	459.10	432.18	588.76
शुद्ध लाभ / हानि	204.74	(56.19)	– 134.81	2.76	–1634.18	48.22
कैश लाभ / हानि	49.96	– 11.84	– 46.31	30.38	28.81	80.72
कुल पूंजी	2191.25	2191.25	2191.25	2191.25	2191.25	2191.25
संचय एवं आधिक्य	1936.86	1880.72	1745.97	1748.77	114.64	162.92
नेट वर्थ	**4436.66**	**4351.82**	**4266.61**	**6433.18**	**2305.89**	**2354.17**

प्रपत्र–ख

2. ऑप्टेल टेलीकम्यूनिकेशन्स लिमिटेड की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है :–

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07 (अनन्तिम)	2007–08 (अनन्तिम)
सकल आय	12.69	1.61	0.30	27.34	187.25	0
शुद्ध हानि	(–) 2024.95	(–) 592.12	(–) 495.89	(–) 293.93	–340.68	–350.97
केश शुद्ध हानि	(–) 2024.11	(–) 589.79	(–) 493.56	(–) 352.26	–334.79	–350.97
कुल पूँजी	2396.71	2396.71	2396.71	2396.71	2396.71	2396.71
संचय एवं आधिक्य	4453.85	4453.85	4453.85	4453.85	4453.85	4453.85
नेटवर्थ	307.71	(–) 253.46	(–) 718.40	(–) 1012.33	–1353.02	–1703.97

प्रपत्र–ग

3. मध्यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी (MAP_IT)

वर्ष	अनुदान राशि रूपये लाख में
2002–2003	30.00
2003–2004	36.00
2004–2005	10.42
2005–2006	25.00
2006–2007	20.00
2007–2008	29.57